

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
द्वारा
"आपदा प्रबंधन में वानिकी की भूमिका"
विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 से 5 मार्च, 2020)
का आयोजन

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा 3 से 5 मार्च 2020 तक नेहरू युवा केंद्र और वन पंचायतों के सरपंचों, वन विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण का विषय है "आपदा प्रबंधन में वानिकी की भूमिका"। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, सर्दियों के तूफान और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान, माल और आजीविका का नुकसान होता है। जंगल विभिन्न माध्यम से भूस्खलन के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तटीय क्षेत्रों में कच्छ वनस्पतियों के जंगल सुनामी और समुद्री ज्वार के वेग को कम करने में सहायक होते हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी की परतों को मजबूती से जकड़े रखती हैं तथा मिट्टी को सहारा देती हैं। पेड़ मिट्टी की नमी के स्तर को कम करके भूस्खलन के जोखिम को भी कम करते हैं। अवरोधन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्राथमिक उपाय हैं। वन क्षेत्रों के निकट जनसंख्या के विस्तार से वनों में आग और मानव-पशु संघर्ष जैसी आपदाएँ सामने आ सकती हैं जो विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में लोगों के जीवन और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हर साल, जंगलों के पास रहने वाले कई लोग तेंदुओं, हाथियों और बाघों द्वारा मारे जाते हैं। अब बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रतिभागियों को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली क्षति से अवगत कराना है और आपदाओं को कम करने में वन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उसका ज्ञान देना है। प्रशिक्षण में जंगल की आग और भूस्खलन की घटनाओं के कारण, विभिन्न रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों के उपयोग तथा सरकार के अन्य विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करके आग और भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में चर्चा की गई जिससे कि बड़े पैमाने पर वन आपदाओं और वन्यजीव संघर्षों को नियंत्रित किया जा सके। प्रतिभागियों को इन विषयों पर अवगत कराने के लिए विभिन्न संस्थानों जैसे उत्तराखंड वन विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखंड और एफआरआई के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री एस.डी. शर्मा, उप महानिदेशक (अनुसंधान), आई.सी.एफ.आर.ई. ने किया। उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार की

आपदाओं (प्राकृतिक और मानव निर्मित) के बारे में प्रतिभागियों को समझाया और वानिकी मध्यस्थता की मदद से इन आपदाओं को कम किए जाने से संबन्धित कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला जिसमें वनों की सहायता से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन और तटीय क्षेत्रों में सुनामी को नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जंगल की आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी नई विधियों और प्रौद्योगिकियों को सीखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वनों की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि देश में जंगल की आग में बढ़ोतरी हो रही है। जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए ग्रीष्म ऋतु से पहले वन विभागों को अच्छी तरह से प्रस्तुत रहना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वनों में पड़ी किसी भी ईंधन सामग्री को ग्रीष्म ऋतु से पहले साफ किया जाना चाहिए जिससे कि आस-पास के क्षेत्रों में आग फैल न जाए। उसके लिए, राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। चालक दल के सदस्यों और स्थानीय समुदाय को आने वाले पीढ़ियों के लिए जंगल को सुरक्षित रखने हेतु आग बुझाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निदेशक श्रीमती आरती चौधरी, प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, व.अ.सं. ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में आपदाओं के शमन के लिए अग्रिम तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने आपदाओं के शमन के लिए विकसित नई विधियों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के चयन पर भी प्रकाश डाला। डॉ. दिनेश कुमार, वैज्ञानिक, व.अ.सं. ने व्यक्त किया कि आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए तकनीकों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि यह कम लागत पर आपदाओं के शमन में कारगर हो। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन में एफआरआई बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। श्री एस.के. थॉमस, सहायक वनवृक्षविज्ञानी, व.अ.सं. ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया

